ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट

*209. श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे:
श्री रुद्रनारायण पाणि:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना ही केन्द्र से, धनराशि की अगली किश्त प्राप्त हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या करण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (च) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रवृत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को मंत्रालय को प्रत्येक योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। राज्यों को वार्षिक प्रगति रिपोर्टें भी भेजनी होती हैं जिनमें वर्ष के दौरान की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है।

2. आमतौर पर ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए राज्यों को दो किस्तों में धनराशि दी जाती है। विगत वर्ष में दूसरी किस्त प्राप्त करने वाले जिलों को बिना किसी शर्त के पहली किस्त स्वयमेव जारी कर दी जाती है। दूसरी किस्त रिलीज करने की शर्तों में एक शर्त यह है कि सभी लंबित प्रगति/निरीक्षण रिपोर्टें भेज दी गई हों।

3. स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के संबंध में मणिपुर और नागालैंड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने प्रगति रिपोर्टें भेज दी हैं।

Progress report on implementation of rural development schemes

†*209. SHRI BALAVANT ALIAS BALAPTE:
SHRI RUDRA NARAYAN PANY††:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the State Governments are required to submit a progress report of the implementation of all the Rural Development Programmes;

(b) if so, the details thereof?

(c) whether it is a fact that some of the States are receiving the next instalment of funds from the Centre without submitting the progress report;

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(e) whether Government have conducted any inquiry in the matter; and

(f) if so, the action taken against the officers found responsible for this?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

As per the Guidelines in force, the State Governments are required to submit Monthly Progress Report of each Scheme to the Ministry States are also required to submit Annual Progress Reports indicating physical and financial progress during the year.

2. Funds for the major rural development programmes ordinarily are released to the States in two instalments. The first instalment is automatically released to the Districts receiving second instalment during the previous year without any condition. One of the conditions for releasing the second instalment is that all pending progress/monitoring reports should have been sent.

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rudra Narayan Pany

3. All the States have submitted the progress reports except the State of Manipur and Nagaland on Swaranjayati Gram Swarozgar Yojana (SGSY).

श्री रूद्रनारायण पाणि: सभापति महोदय, मैंने प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह जी से जितने स्पष्ट उत्तर की आशा की थी, उतना स्पष्ट उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने पहले पूछा था कि क्या राज्य सरकारों को सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, इस संबंध में उन्होंने उत्तर दिया है कि आवश्यक होता है। प्रश्न ''ख'' में मैंने पूछा है कि तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि ''क'' का उत्तर हां है, तो ''ख'' में कम से कम दो साल का ब्यौरा दिया जाना चाहिए था। अगला प्रश्न था कि क्या कुछ राज्यों को, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना ही केन्द्र से धनराशि की अगली किस्त प्राप्त हो रही है, इसका उत्तर भी नहीं दिया गया। सभापति जी, प्रो॰ रघुवंश प्रसाद सिंह कम से कम इस प्रश्न को स्पष्ट करें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि राज्य सरकारों के द्वारा मासिक प्रतिवेदन भेजने के बाद राशि रिलीज की जाती है, उसका उत्तर हां में दिया गया है। हर राज्य से 20 तारीख के करीब प्रगति प्रतिवेदन आता है। किसी-किसी राज्य में देर हो जाती है, लेकिन मासिक प्रतिवेदन अवश्य भेजा जाता है। इसके मुताबिक ही पैसा रिलीज किया जाता है। ग्रामीण विकास की जो आठ योजनाएं हैं, उनमें राशि दो किस्तों में रिलीज की जाती है। प्रथम किस्त रिलीज करने के बाद दूसरी किस्त पाने के लिए जब साठ प्रतिशत से अधिक खर्च करने का प्रतिवेदन आता है, तब ऑडिट रिपोर्ट की छानबीन की जाती है और दूसरी किस्त रिलीज की जाती है। अगले साल अगर ओपनिंग बैलेंस बीस प्रतिशत से ज्यादा न रहे तो अगली राशि रिलीज करते हैं। इसके बाद दूसरी राशि रिलीज करते हैं इनके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं। कहीं किसी नॉर्म का उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने बताया है कि केवल एक योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मणिपुर और नागालैण्ड की ओर से अभी तक मासिक प्रतिवेदन नहीं आया है, बाकी आठ योजनाओं के संबंध में सभी राज्यों से मासिक प्रतिवेदन आता है और राशि रिलीज की जाती है। इस साल के बजट में हमने साठ प्रतिशत से अधिक राशि रिलीज कर दी है। यह राशि गांव में खर्च हो रही है और गांव का काम हो रहा है।

श्री रूद्रनारायण पाणि: सभापति महोदय, उत्तर के भाग दो में यह लिखा हुआ है कि विगत वर्ष में दूसरी किस्त प्राप्त करने वाले जिलों को, बिना किसी शर्त के पहली किस्त स्वयंमेव जारी कर दी जाती है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि इसमें जिलों को जो शब्द लिखा गया है, क्या केंद्र जिलों का सीधे राशि देता है या राज्य के माध्यम से देता है?

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, एस॰जी॰आर॰आई॰, जो वेजिस एम्प्लोएमेंट स्कीम है और जो इंदिरा आवास योजना है, यहां से सीधे डी॰आर॰डी॰ए॰ को पैसा जाता है। डी॰आर॰डी॰ए॰ से पंचायत के पास जाता है, तदनुसार खर्च होता है ...(व्यवधान)... इसमें डी॰आर॰डी॰ए॰ में जिला पंचायत को बीस प्रतिशत ...(व्यवधान)... ग्राम पंचायतों को पचास प्रतिशत ...(व्यवधान)... दिया जाता है।

श्री सभापति: बैठिए। Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Construction of tunnel below Rohtang pass

†*206. SHRI KRIPAL PARMAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the latest status of the work for constructing a tunnel below Rohtang pass near Manali in Himachal Pradesh;

(b) the proposed expenditure on this for the current year alongwith the expenditure incurred so far and total expenditure estimated for constructing the tunnel; and

(c) whether its construction will be completed during the Tenth Five Year Plan?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) It is proposed to construct a tunnel at Rohtang to provide an all weather road to Leh.

In May 2002 it was decided, as a first step, to construct access roads to both the North and South portals of the proposed tunnel at Rohtang at a cost of Rs. 30 crore. Two access roads were to be constructed of 2.7 kms (North Portal) and access road to the South portal of 23.8 kms. The access road to the North portal of the tunnel has almost been completed and 23.46 kms. of the access road to the South portal has been completed.

A sum of Rs. 30 crore has been utilized till March 2004. The amount spent during the current financial year is Rs. 14.82 crore in addition.

†Original notice of the question was received in Hindi.